दिनांक–21.09.2016 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के कार्यान्वयन से संबंधित बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – उपस्थिति सूची के अनुसार।.

<u>बैठक की कार्यवाही</u> –

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

2– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजे जानेवाले प्रतिवेदन से संबंधित पत्र–2210 दिनांक–17.08.2016 की प्रति उपलब्ध कराते हेतु संबंधित विभाग के उपस्थित नोडल पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन भेजी जाए ताकि सगेकित प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजी जा सके ।

3– भारत सरकार को अनु0 जाति उपयोजना एवं अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत विगत पाँच वर्षो 2012–13 से 2015–16 तक प्रतिवेदन भेजने से संबंधित पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजने का अनुरोध किया गया।

4– विगत तीन वर्षो में अनु0 जाति उपयोजना एवं अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत योजना उद्व्यय के विरूद्ध ली गई योजनाओं का प्रक्षेत्रवार/योजनावार भैतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के आलोक में अनु0 जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत विगत तीन वर्षो वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 का प्रतिवेदन कृषि विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य निदेशालय एवं मत्स्य निदेशालय) द्वारा प्रतिवेदन बैठक में उपलब्ध कराया गया एवं विगत दो वर्षो वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 का प्रतिवेदन पंचायती राज एवं सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। सहकारिता विभाग द्वारा अनु0 जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत एक ही राशि अंकित किया गया है। जिन विभागों द्वारा प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराए गए है उस विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो–तीन दिनों में प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा।

5– वित्तीय वर्ष 2016–17 का विभागवार अनु0 जाति उपयोजना (789) एवं अनु0 जनजाति उपयोजना (796) के तहत प्रक्षेत्रवार बजट उपबंध से संबंधित प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई तथा अनुरोध किया गया कि अगर बजट के पश्चात बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय में कोई अन्तर है तो उसकी सूचना भेजी जाए।

6– वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं में अगर Gap Filling के तहत राशि प्रावधान करने की आवश्यकता है तो संबंधित परियोजना प्रस्ताव के साथ मांग पत्र इस विभाग को भेजी जाए ताकि तदनुसार परियोजना प्रस्ताव

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अनु0 जनजाति के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अनु0 जाति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जा सके।

7– वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को परियोजना प्रस्ताव भेजा जाना है। संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं की विशेष उपलब्धि हो तो उस योजना का Success Story भेजी जाए ताकि भारत सरकार को भेजे जानेवाले परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजी जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः सं0सं0–08 / निदशालय / बैठक–08–05 / 2016– 5493 पटना, दिनांक– 23.09.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग / पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग / सहकारिता विभाग / शिक्षा विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग / उर्जा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / उद्योग विभाग / श्रम संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / पंचायती राज विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / योजना एवं विकास विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / पथ निमार्ण विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / गन्ना उद्योग विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 23/9/16

ज्ञापांकः सं0सं0–08 / निदशालय / बैठक–08–05 / 2016– 5493 पटना, दिनांक– 23.09.16

प्रतिलिपिः– सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 23/9/16

ज्ञापांकः सं0सं0–08 / निदशालय / बैठक–08–05 / 2016– 5493 पटना, दिनांक– 23.09.16

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी विभागीय पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 23/9/16

ज्ञापांकः सं0सं0-08/निदशालय/बैठक-08-05/2016- 5493 पटना, दिनांक- 23.09.16

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 23/9/16

दिनांक 21.09.2016 को निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में अनु0जाति उपयोजना एवं अनु0जनजाति उपयोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक की उपस्थिति :–

कमांक	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	मोबाइल न0 / ई0मेल न0
1	2	3	4	5
1	[illegible]	[illegible]	[signature] 21/9	9471007402 director dairy.[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[signature] 21/9/16	9470001253
3	मुकुल कुमार OSD	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	[signature] 21/9/16	9199212871
4	गुफरान अहमद OSD	पंचायती राज विभाग	[signature] 21/9/16	8544420004
5	~ P. Raul A. Director Cane Industry	Cane Industry	[signature] 21-9	9471007229
6	R.S. Prasad Under Secretary	Urban Development & Housing Deptt.	[signature] 21/9/16	9905208226
7	Vidyarthi Dy Dir. Industry	Deptt of Industry	[signature] 21/9/16	9304024288
8	Richa Kamal Deputy Sec Cooperative	Cooperation	[signature] 21/09/16	7070523115
9	M.K. Choudhary D.C.F.	ENV. & Forest Dept Bihar	[signature]	9693519109
10	P.P. Verma E.E	Water Resources Deptt.	[signature]	9431647566
11	[illegible]	Food & [illegible]	[signature]	9534575212
12	Suman Kumar	Fisheries Directorate	[signature]	9473191554
13	Dip Chand Prasad Joint Director	Planning and Development	[signature]	8544128137
14	Nityanand Lal Assistant Director	Education Department	[signature]	8544412194
15	Yogendra Pd Yadav	Minor Water Resources Department	[signature] 21.09.16	9431882219
16	SHAILESH KUMAR	Joint Secretary Labour Resource	[signature] 21/9/16	9430980734
17	P Ram	Adm Cum Add. Secretary Agriculture	[signature] 21/9/16	9431818783
8				
9				
10				
11				
12				

महत्वपूर्ण/स्मार पत्र

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति,कल्याण विभाग

सं0–2 जी0(रा0 आयोग) अनु0 जाति–20/2011–पार्ट–1– 2210

Email

प्रेषक,

सुरेश पासवान,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव
गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/उद्योग विभाग
योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग
कृषि विभाग/लघु जलसंसाधन विभाग/सहकारिता विभाग
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग
समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/पथ निर्माण विभाग
स्वास्थ्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पंचायतीराज विभाग
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/ जलसंसाधन विभाग
श्रम संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/विधि विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
पुलिस महानिरीक्षक, (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग।
महानिदेशक, अभियोजन, गृह(विशेष) विभाग।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार महादलित विकास मिशन, पटना।

पटना, दिनांक– 17.8.16

विषयः– **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई प्रश्नावली के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–4001 दिनांक–10.05.16, पत्रांक–1579 दिनांक–08.06.16 एवं पत्रांक–1978 दिनांक–27.07.16।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र का सदर्भ करना चाहेगें।

उक्त पत्र के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या–11/04/NCSC/2014–सी0 सेल दिनांक–14.03.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गई प्रश्नावली संलग्न करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अबतक अप्राप्त है।

इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से लगातार स्मार पत्र प्राप्त हो रहे है। आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नावली के अनुसार सुस्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गई है।

अतः प्रश्नावली की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन दिनांक–25.08.2016 तक इस विभाग के ई–मेल **secy-welfare-bih@nic.in** पर /विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भेजी जा सके।

अनु0–यथो0

विश्वासभाजन

17/8/16

(सुरेश पासवान)
सरकार के विशेष सचिव।

By Spl. Messenger

100

Phone : 2540285, 2541912
Fax : 0612-2540285
Toll Free Number : 1800 1800 345
E-mail ID : dirncsc-bih@nic.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

राज्य कार्यालय, बिहार एवं झारखण्ड

STATE OFFICE, BIHAR & JHARKHAND

189-बी, श्रीकृष्णापुरी, पटना-800 001
189-B, Srikrishnapuri, Patna - 800 001

No. 9/1/2016--R.U.

Date / दिनांक 21/03/2016

To,

The Chief Secretary,
Govt. of Bihar,
Patna.

Sub : State Level Review Meeting to be taken by the national Commission for Sch. Castes, Govt. of India, New Delhi - regarding.

Sir,

I am directed to refer to letter No. 11/04/NCSC/2014-C.Cell dated 14-03-2016 (copy enclosed for ready reference) from the National Commission for Sch. Castes Govt. of India, New Delhi on the above subject and to say that the Commission has proposed to hold the State Level Review Meeting. For the purpose, the Commission has desired to have information in the prescribed questionnaire (enclosed).

It is, therefore, requested that the latest information/data in the enclosed prescribed questionnaire may kindly be furnished to the Commission Hqrs immediately with a copy of the same to this office for information and necessary action.

Yours faithfully,

Encl: As above

(S. K. Singh)
Senior Investigator

Copy forwarded for information and necessary action to the Secretary, SC & ST Welfare Department, Govt. of Bihar, Patna with a copy of letter referred to above.

Senior Investigator

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और आपसे आशा की जाती है कि आप अनुबंधित समय के भीतर उत्तर दें, अन्यथा आयोग इस मामले को निपटाने में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने को बाध्य होगा ।
Commission is a Constitutional Authority. You are expected to respond within stipulated time, failing which Commission will be constrained to invoke constitutional powers to deal in the matter.

No. 11704/NCSC/2014-C.Cell
Government of India
National Commission for Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak [illegible]
Khan Market, New [illegible]
Dated [illegible]

To

The Chief Secretaries of the State of
Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, [illegible]
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Sikkim & Telangana.

Sub: State Level Review Meeting to be taken by National Commission for Scheduled Castes, Government of India – regarding.

Sir,

As you are aware that the fourth National Commission for Scheduled Castes (in series) has been constituted with Dr. P.L. Punia, Chairman, Dr. Raj Kumar Verka, Vice-Chairman, Shri Raju Parmar, Member, Shri Ishwar Singh, Member and Smt. P.M. Kamalamma, Member. The Commission has desired to hold the State Level Review Meetings of the above-mentioned States/UTs. A copy of the prescribed questionnaire is enclosed for necessary action. The questionnaire may also be downloaded from the website of this Commission : www.ncsc.nic.in

It is requested that the latest information/data in the enclosed prescribed questionnaire may be furnished to this Commission for discussion during the State Level Review Meeting.

Thanking you,

Yours faithfully,

(G.K. Thorat)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Encls.: As above.

Office of the Director
For Sch. Castes
[illegible]
RECEIVED ON 16/03/2016
DIARY No.

QUESTIONNAIRE FOR INFORMATION FROM STATE GOVERNMENTS TO [illegible]
SAFEGUARDS AND INITIATING DEVELOPMENT PROGRAMMES [illegible]

General

Name of the State:

Total Number of Districts:

Villages:

Blocks:

Police Stations:

Population			Sex [illegible]		Ratio [illegible]
SC Population (%)					
ST Population (%)					
Literacy rate	Total:	Male:	Female:	Male:	Female:
Literacy rate: SC		Male:	Female:	Male:	Female:
Literacy rate: ST		Male:	Female:	Male:	Female:
Total No. of BPL Families					
Total No. SC BPL Families:					

No. of Schools in SC localities:

No. of Hospitals in SC localities:

No. of SC Hostels:

No. of SC Hostels (Girls)

No. of coaching centre for SC:

Development

1. What are the specific needs and problems of SC communities in your State?

   Details indicating the funds allocated to the State out of SCA to SCP and their utilization during each year of the 12th Five Year Plan upto 2013-2014 may be furnished. Reasons for non utilization of funds or diversion of funds for other purposes should be clearly spelt out.
   Give the details of the schemes under which the SCA was spent in the State. The details of expenditure schemes wise may be given for last three financial years 2011-12 to 2013-2014

(Rs. in Crore)

	Name of the Scheme	Funds allocated	Expenditure incurred	Non-utilized funds	Funds diverted to other heads
			[illegible] SCA to SCP		
Total 12th Plan					
2011-2012					
2012-2013					
2013-2014					

Whether any study has been conducted to know the manner of utilization of the funds and the desired results/achieving specific targets? Whether the State Government has sponsored such studies by independent research organizations of repute such as [illegible] Institute of Social Sciences etc.

Provide details of schemes which are exclusively for SC people.

(a) Whether any appraisals of the working of Special Component Plan (Scheduled Caste Plan) under 12th Five Year Plans were made, if so, what were the financial and physical targets achievements?

(b) Whether there was any shortfall under any programme, if so, what are the factors responsible for slow progress?

(c) How were those difficulties tackled during the currency of the 12th Five Year Plan? What are the achievements in Annual Plan 2013-2014?

(d) Year-wise allocation/expenditure of SCP out of State Plan funds for the each year for the during 2011-12

(e) Whether the funds allocated under the SCP have been utilized for the purpose other than it is allocated. Details thereof in the following format:

	Total Plan Outlay	State Outlay	Flow to SCP		
			Outlay	Amount Diverted to other heads	Details where spent with reasons to do so.
Total 12th Plan					
2011-2012					
2012-2013					
2013-2014					

(f) Whether any study has been undertaken to know the manner of utilization of SCA? If so, salient findings may be indicated, if not whether State Government is proposing to sponsor such studies to any independent Research Organization. Details thereof.

3. **Please state**

a) Whether the existing machinery for formulation and implementation of the SCP is adequate and effective? If not, what further steps are needed to strengthen the existing set-up? What measures have been adopted to secure trained personnel for implementation of programme of socio-economic development of SCs in inaccessible/difficult areas?

b) What is the role played by voluntary organizations/agencies in disseminating information and implementation of programmes for development of SCs. What Steps were taken to make their association fruitful?

c) What are the Scheduled Castes Special schemes undertaken for development of agriculture, minor irrigation and soil conservation, horticulture, animal husbandry, pottery and fisheries for rural artisans which if taken up intensively would have greater impact on socio-economic development of SCs? Details of each scheme, funds allocated and spent, number of beneficiaries and short fall in the target fixed and reasons thereof (year-wise) for the last 3 years.

Name of the State/UT________________

________________% SC population as per 2011 Census

Year	Total State Plan Allocation	Total State Plan Exp	SCSP Outlay	SCSP Exp Actual	%age of SCSP allocation to the State Plan Allocation	%age of SCSP Exp. To the State Plan Exp.	General Schemes under SCSP		SC Specific schemes under SCSP		%age of SC [illegible] to total SCSP Exp	%age of allocation [illegible] to the total [illegible] allocation	%age of Exp under SC specific schemes [illegible] total [illegible] Exp	%age of [illegible] allocation
							Allocation	Exp.	Allocation	Exp.				
2011-12														
2012-13														
2013-14														

d) What has been the impact of anti-poverty and employment generation schemes/programmes such as SGRY, SGSY, IAY and [illegible] for the benefit of the SCs in the State? Details of each scheme, funds allocated [illegible] number of beneficiaries and short fall in the target fixed and [illegible] for the last [illegible] years.

e) What have been the types of schemes and the sectors in which self employment under SGSY benefits have been provided in the last 5 financial years. What has been the per-capita investment in general under this programme and the per capita investment for the SC population in particular.

	Name of the Scheme	Sectors in which self employment under the SGSY benefits provided	Per capita investment in gene	Per capita investment for the SCs population in particular	Short fall and reasons thereof
Total 12th Plan					
2011-2012					
2012-2013					
2013-2014					

Education

4.

(a) Please state the problems and needs regarding education of SCs. Whether the measures taken by the State Government and Central Government to meet the needs are adequate? Do you suggest any further schemes to strengthen the educational programmes covering the following issues amongst others:-

(b) What is the teacher-pupil ratio in schools located in *SC dominated villages* and cluster areas vis-à-vis in other parts of the State?

(c What is the total and the rate of drop outs (Male and Female children) in the primary, middle and the secondary level viz-a-viz overall drop outs and reasons thereof for the last five financial years 2009-10 to 2013-14? What action has been taken to reduce the drop out's rate of SC students and results so far.?

Drop out	Primary				Middle				Secondary			
	General		SC		General		SC		General		SC	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Total 12th Plan												
2011-2012												
2012-2013												
2013-2014												

(d) Is Mid day meal scheme implemented in the Schools? What is the mechanism to monitor the quality of food?

(e) What are the systemic checks that are introduced by the State, to ensure SC students who are studying in the un-aided institutions do not fleece the SC students in the form of Tuition Fees. What is the level of reimbursement? Has any study been conducted in this regard for rationalization of the fees? What are the systemic checks developed by the State, so that educational institutions in the garb of development do not indulge in profiteering from Students including SC's?

(f) What is the Annual turnout of Graduates vis a vis that of SC's. What is the total number of Professional Graduate Turn out annually vis- a- vis that of SC's. Data for the last 3 years in the following format:

year	Total number of graduates	SC graduates	Total number Prof. graduates	SCs out of them.

(g) Please give details of the Special Coaching & Training offered to the students to appear for PSC, UPSC & other Competitive Exams? What had been the result of these institutions for the last five years 2010 to 2014 respectively in the various examinations? Is there any institution in the State which offers appropriate training to SC students to prepare for CAT & other related entrance examinations? What has been its success rate? How much expenditure is incurred on each of these students? Is there any voluntary organizations helping the SC students in achieving the above objective? Give details thereof if any?

Year	Name of the Institution	Type of coaching/training	Total number of SC beneficiaries	Success rate	Amount sanctioned for each training

(h) What is the time frame in which the tuition fee reimbursement to educational institution from the Social Welfare Department takes place? Is there any outstanding payments pending to students for the past 03 years? If yes give details thereof?

(i) Is the tuition fees reimbursements done through cash or through Bank accounting? If cash, then when the State wants to introduce payments through Banks?

(j) Does the students in professional colleges are made to pay the fees and reimbursement made if so, what is the time frame. Has the administration examined the same?

(k) Please give details of Educational Schemes for SC girls and boys funded by the State Government as well as by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Ministry of HRD, Departments of Elementary, Secondary & Higher Education and the Literacy Mission including the Sarva Siksha Abhiyan of the Govt. of India may be furnished including physical and financial targets and achievements during the last 5 financial years from 2011-12 to 2013-2014.

(l) Whether there are any special schemes for the educational requirements of Safai Karamchari section of the Society?

(m) Whether any pockets of SC concentration, where the literacy of the SC women is less than 10 percent has been identified? If so, details thereof. Whether the district administration has set up educational complexes in these areas with the grants received from the Govt. of India? If so the details there.

(n) Have you noticed any shortfalls in the implementation of the Sarva Siksha Abhyan?

(o) What is the number of SC teachers in Primary/Middle/High Higher Secondary Schools in the State out of total number of teachers?

(p) What is the annual turn out of graduates in State in rural/urban areas in the State and how many of them belong to SCs?

(q) Details of the number of seats reserved in professional and other institutions and the number actually filled up year-wise. (last five financial years i.e. 2011-12 to 2013-2014).

(r) Are any concessions given to SCs to fill up the reserved seats? If yes, what type of concessions? (Details may be given)

(s) Details of Special Coachings/Trainings organized and the results of special steps taken in this regard by the State Government and DGE&T, Govt. of India.

(t) Details of provisions and enrolment of SC students in institutions in general at Primary and Secondary Schools.

(u) Details of Educational Institutions for SC as per the format below may be furnished.

Type of Institution	No. of Institutions run by Education Deptt.			No. of Institutions run by Social Welfare Deptt.			No. of Institutions run by the NGOs rearing funds of the State Govt.			Grand Total		
	R	NR	T	R	NR	T	R	NR	T	R	NR	T
Primary												
Secondary												
Senior Secondary												

R-Residential : N.R.-Non-Residential : T-Total

(v) Details of Educational Schemes for SC girls and boys funded by the State Government as well as by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Ministry of HRD, Departments of Elementary, Secondary & Higher Education and the Literacy Mission including the National Literacy Mission of the Govt. of India may be furnished, including physical and financial targets and achievements during the last 5 financial years from 2009-2010 to 2013-2014.

(w) **The rate of Scholarship/stipends (including details of income ceiling of parents) provided to the students at pre-matric and post-matric levels may be indicated and financial and physical targets and achievements for the last five financial years from 2009-2010 to 2013-2014.**

It would also be appreciated if any other information which the State Government may like to give regarding initiatives taken by them for the development of SCs etc. is included in the reply.

(x) Whether pockets of SC concentration where the literacy of the SC women is less than 2 percent have been identified? If so. details thereof. Whether the State Govt. have set up educational complexes in these areas with the grants received from the Govt. of India.

(y) Any other innovative schemes design by the State Government for the welfare of SC children details thereon.

Health

5(a) Please state if the medical facilities available in the rural areas/backward areas and trained personnel in the Govt. dispensaries are adequate. If not what measures have been taken to attract the trained medical personnel? What is the population and area covered by PHC's sub-centers in rural/backward areas and how does it compare with the areas in general.

(b) How many SC dominated villages in the State which have no drinking water sources? What are the schemes to provide drinking water in those villagers?

(c) Any special programmes/Schemes formulated under the NRHM and by the State Government on its own for the SCs details thereof.

Hostels

6. (a) How many hostels for SC students in schools and college have been set up in the State and have been mainly occupied by them and what is the capacity of each hostel? *How many hostels provide common kitchen/dining hall facilities? How many hostels have got full basic infrastructure facilities?* Are there any hostels set up for SC girls? Details thereof. Has any assistance been obtained from the Ministry of Social Justice & Empowerment under the Centrally Sponsored Scheme for the construction of Girls Hostel(s) for SCs in educationally backward districts? Please provide the information in the proforma as under:-

Total No. of Hostels for SCs		No. of Hostels having common kitchen/dining hall facilities	Funds received from Social Justice & Empowerment, Govt. of India for construction of Hostels in last three years (year-wise)	Amount spent and balance if any with the reason for non-utilization of funds in last three years (year-wise)	No. of Hostels not functioning due to shortage of staff.
Boys	Girls				

(b) What are the stipends payable to the boarders in the hostel? Are there any facilities for giving coaching to the weak SC boys and girls in the hostels?

© Whether any survey/study conducted on the working of these hostels and what is the result with specific reference to the SCs.

Housing

7. Please state the number of houses/house sites allotted to SCs in the State during the last 5 *financial years from 2011-12 to 2013-2014 out of total houses/house sites allotted in the State under Indira Gandhi Awas Yojana and other Housing Schemes both under the State and the Central Government Schemes. Is it in tune with SC population/percentage? Reasons for short fall, if any. Progress under the JNURM.*

%age of SC population without Pucca House	%age of SC population given houses under different schemes	Plan to give Pucca house to every family in how many years
(1)	(2)	(3)

Land

8. How much waste land/surplus land has been allotted to and taken possession of by landless agricultural labourers belonging to SCs during the last five financial years from 2011-12 to 2013-2014. What is the average size of land allotted?

What is the %age of SCs among workers under MNREGA	How many got employment for full 100 days in the MNREGA	How many were given daily allowance in lieu of work not provided on demand
(1)	(2)	(3)

9. What is the Government Policy to rehabilitate displaced persons when their land is acquired for development project? What are the guiding principles of such policy? Whether any compensation was given with special reference to the SCs.

10. (a) What legislative and executive measures have been taken to check land alienation of SCs with specific reference to the following:-

(b) How many land alienation cases have been detected each year during the last five financial years from 2011-12 to 2013-14. In how many cases action under POA Act taken.

(c) What steps have been taken to dispose off such cases?

(d) How many cases have been disposed off so far as on 1.4.2014?

11. Details of various schemes like SGSY, MNREGA, PMRY, SGRY etc. and number of SCs benefited during last three financial years. Whether payment under the MNREGA is made through Banks or in cash? What are the systematic checks to ensure that the amount is spent appropriately? Has the schemes been subjected to any audit by the CAG if so what are there observations and action taken thereon.

Forestry

12. (a) The extent of participation promoted among SCs in the field of Social Forestry? Its impact on their economy and living conditions may be given.

(b) Has your State experienced any constraint/difficulty in implementing the National Forest Policy, 1988? What are those measures suggested in this direction for its proper implementation.

© How far the SCs are entitled to collect forest produce for their domestic consumption and sale? Has this entitlement been reviewed in the recent past and its impact with details.

Marketing

13. (a). Please state what institutional arrangements have been made to regulate the marketing of produce collected by SCs from reserved forest or forest under occupation of SCs, agricultural produce and its marketing?

b. What are your suggestions to improve functioning of State institutions engaged in collection and marketing of minor forest produce, agricultural and other produce?

Training

14. What are the types of training facilities provided to Scheduled Castes in the field of:-

i. Agriculture

ii. Minor forest produce collection & marketing.

iii. Cooperative ventures

iv. Dairying & animal husbandry

v. Artisanship

vi. Weaving, etc.

15. (a) Skill Development Programmes/Trainings to SCs by various Government Agencies should cover not only the training aspects but also the efforts to over see by the concerned candidates get income generating job after training. Details of number of trained SC personnel and job acquired out of them during last three financial years.

year	Type of training	No. of SCs beneficiaries	No. of SCs beneficiaries got employment

(b) Please give the details of the self help groups (SHG) and its institutional finance assisted system in the state? How many new Micro enterprises have been started with the Rural SC population in the past 03 years giving self employment & creating sustainable development using their local skills? The above data may be given in respect of each district wise.

Year	Details of SHGs	Source of Institutional Finance	No. of new Micro Enterprises started with Rural SC population for self employment using their local skills

(c) In all the districts of the States the Rural Employment Guarantee Scheme is being implemented. How many total man hours have been given during last five financial years and total number of SC beneficiaries year wise.

Name of the districts	Total No. of man hours given	No. of man hours given to SCs	No. of SCs beneficiaries

Atrocities

16. (a) Please state the number of cases of harassment/atrocities perpetrated on SCs during the last five financial years from 2011-12 to 2013-14 under various provisions of IPC, the PCR Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and their disposal by police and courts as per Statements I to IV.

(b) Cases registered under Section 156(3) of Cr.P.C. in last three years against the SCs in the following table:-

S.No.	Nature of offence	No. of cases registered during the year		
		2011	2012	2013
1.	Murder			
2.	Rape			
3.	Arson			
4.	Grievous Hurt			
5.	Other offences under the IPC			
6.	Total:			

© No. of cases referred to the State by the National Commission for Scheduled Castes in following format:-

Year	Reference No. and date of the case referred to by the NCSC	Action Taken by the State Government and the present status in each case.
2011		
2012		
2013		

(d) Please state the various steps taken/proposed to be taken to prevent recurrence of such crimes and machinery set up at the State, District and local level to deal with crime against Scheduled Castes.

(e) Has any Special Cell/Police Station been set up in the sensitive areas to deal with such cases more effectively and if not, the reasons thereof?

(f). Whether any survey/study conducted into crimes/atrocities prone and sensitive areas? What are the indications there from and measures taken to check recurrence of atrocities in those areas.

(g). Functioning of the Special Courts, set up under Section 14 of the SCs and the STs (POA) Act, 1989.

(h). Machinery set-up at the State, district and local level to deal with the crimes against SCs?

(i). No. of cases registered under PCR Act, 1955 and the SCs & STs (POA) Act, 1989 and withdrawn by the Government? If yes, please give details along with the reasons for such withdrawal.

Atrocity case registered under POA Act, 1989.

Year	Cases brought forward	Cases Registered for Investigation	Cases Charge sheeted	Cases Pending Investigation
2011				
2012				
2013				

II

Disposal of cases by Courts under POA Act, 1989.

Year	Cases brought placed for previous year	Cases registered during year	Cases disposed/ withdrawn	Acquittal	Conviction	Total 4+5+6	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
2011							
2012							
2013							

(j). Please furnish details of monetary relief provided to the number of Scheduled Caste victims of atrocities during the last five financial years from 2011-12 to 2013-14.

(k) How much average time is taken to provide the relief from the date of registering the FIR.

(l). What were the allocations and the expenditure from the State Plan and Central Assistance under the Centrally Sponsored Schemes for implementation of PCR Act, 1955 and SCs&STs (POA) Act, 1989 during the last five financial years 2011-12 to 2013-14.

Year	Total funds received	Amount spent	No. of SCs beneficiaries	If additional funds required. Details thereof.

(m). Is the sensitive areas identified? What is the machinery to tackle the atrocities on SCs in those areas.

(n). Is the State and District Vigilance Committee meetings are held periodically? If so, action taken on the minutes of the meetings of the Vigilance Committees during last three years.

Year	Date of meetings of the State Level Vigilance Committee	Decisions taken and action taken on the decisions	Date of meetings of the District Level Vigilance Committee	Decisions taken and action taken on the decisions

Bonded Labour:

17.(a) Has any survey/study been conducted on the incidents of bonded labour in your State?

(b) What steps have been taken to abolish bonded labour system?

© How many bonded labourers have got relief and rehabilitation during the last five financial years from 2011-12 to 2013-14?

Year	Total no. of Bonded labourers	No. of Bonded labourers got relief	No. of Bonded labourers rehabilitated	No of bonded labourers who relapsed to the bonded labour system after rehabilitation	Reasons thereof and steps taken to check the same with details.

Manual Scavenging

18. (a) Whether the practice of manual scavenging is still continuing in the State? Details thereof.

(b) Status of implementation of Probation of Employment as Manual Scavengers & their Rehabilitation Act, 2013(MS Act, 2013) the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 2013.

Service Safeguards

19. (a) Prescribed quota of reservation in services for Scheduled Castes:

In direct recruitment In promotion

(b). Whether there is any provisions for the most backward among the Scheduled Castes? If so, details thereof.

© How many Safai Karamcharies are among Class IV employees?

(d) Has the State/UT promulgated any Act governing the reservation for SCs in services/Posts? If so, a copy of the Act along with up-to-date set of other related instructions/orders may be supplied.

(e) If no formal Act on the above subject exists, up-to-date, set of orders/instructions governing the reservation for Scheduled Castes may be furnished.

(f) What is the machinery/checks devised to ensure that the reservations made in favour of Scheduled Castes are actually implemented?

(g) Is there any Act providing punishment to officers who violate the reservation policy for Scheduled Castes? If so, a copy of such Act may be given.

(h) Are there instances where persons have obtained employment under the State Government on the basis of false caste certificates? If so, indicate the number of such cases, action taken and present position of each case. Also indicate the steps taken to avoid recurrence of such instances. Data for the last five years in the format below:-

Year	No. of cases	Details of cases	Action Taken and present position of each case	Steps taken to avoid recurrence of such instances.

(i) Has the State/UT set up any Committee for scrutiny of false caste certificates? If so, what is the composition of the Committee, whether the decision of the Committee is final and the procedure followed by the Committee may also be indicated? What is the pendency of cases in respect of SCs regarding verification before the Castes Scrutiny Committee.

(j) What are the measures that are taken by the State Government to ensure that children in the schools get domicile certificate and also castes certificate easily.

(k) What steps the State has taken to ensure the identification of SC Employees who change there religion, other than to Sikh and Neo Buddhist, and at the same time avail the reservation benefit meant for SCs.

(l) Has the State formulated any Act for regulating and governing the reservation in services for SCs if yes, details thereof.

(m) Please indicate the number of backlog vacancies for Scheduled Castes identified and number of vacancies filled up by the Special Recruitment Drives (SRD) launched from time to time. Figures may be given for all categories of posts separate for each SRD giving the period covered by each SRD.

Year	No. of backlog vacancies	No. of backlog vacancies filled	No. of backlog vacancies remained unfilled	Reasons thereof

Details of Spl. Recruitment Drive	No. of backlog vacancies proposed to filled up	No. of backlog vacancies cleared	No. of backlog vacancies unfilled after SRD	Action proposed to be taken to clear the backlog

(n) Any special training provided for filling up of the reserved vacancies. If yes, details.

(o) Please give the number of employees sent for specialized training abroad and within the country during the last five financial years from 2009-2010 to 2013-2014 and the number of SC candidates amongst them in each case.

Year	No. of employees sent for specialized training in India	No. of SC beneficiaries	No. of employees sent for specialized training abroad	No. of SC beneficiaries

(p) What is the procedure followed by the State Government for de-reservation of vacancies reserved for Scheduled Castes.

(q) What is the machinery devised for the prompt redressal of grievances of Scheduled Castes employees at various levels in the State.

® Please furnish a statement showing the strength of employees in the State/UT and as on 1.4.2014 in the following tables. (Information in respect of Sweepers may be given separately.)

Group of Posts	Total No. of Employees	No. of SC Employees	Percentage of SC Employees	Short falls of SC Employees	Remarks
A					
B					
C					
D					
Sweepers					

(s) What is the actual representation of SCs in the State Public Sector Enterprises (latest position available).

Group of Posts	Total No. of Employees	No. of SC Employees	Percentage of SC Employees	Short falls of SC Employees	Remarks
A					
B					
C					
D					
Sweepers					

STATEMENT SHOWING CASES REGISTERED WITH THE POLICE UNDER DIFFERENT NATURE OF ATROCITIES ON SCHEDULED CASTES UNDER THE SCST (POA) ACT, 1989.

STATEMENT-I

S.No.	Nature of offence	Scheduled Castes			Remarks
		2011	2012	2013	
1	2	4	5	6	
1.	Murder				
2.	Grievous Hurt				
3.	Rape				
4.	Arson				
5.	Other Offences				
(a)	Other IPC				
(b)	Other POA				
(c)	PCR				
	Total:				

STATEMENT SHOWING DETAILS OF CASES REGISTERED AND DISPOSED OFF BY THE POLICE UNDER THE PROTECTION OF CIVIL RIGHT ACT, 1955

STATEMENT-II

S.No.	Year	Cases brought forward	Cases registered during the year	Total	Cases chalaned	Cases closed after investi-gation	Cases pending	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2011							
2.	2012							
3.	2013							

STATEMENT SHOWING DETAILS OF CASES REGISTERED AND DISPOSED OFF BY THE POLICE UNDER THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITY) ACT, 1989.

STATEMENT-III

S. No.	Year	No. of SC cases brought forward	No. of SC cases registered during the year	Total No. of SC cases	No. of SC cases challenged	No. of SC cases closed after investigation	No. of SC cases pending	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2011							
2.	2012							
3.	2013							

ANNEXURE [illegible]

STATEMENT OF SHOWING DISPOSAL OF CASES INVOLVING SCs BY THE SPECIAL COURT DURING YEARS 2011,2012 AND 2013.

S.No.	Year	No. of Cases				No. of Cases			
		Brought Forward	Received	Total	Disposed	Ending in Acquittal	Ending in Conviction	[illegible]	[illegible] pending at close of year
1	2011								
2	2012								
3	2013								

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
8डी0–(TSP)-17–10/2016– 4539

प्रेषक,

वीरेन्द्र,भा0प्र0सेवा,
निदेशक ।

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव,
कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन, विभाग /सहकारिता, विभाग /शिक्षा, विभाग /वन एवं पर्यावरण, विभाग /उर्जा, विभाग /पर्यावरण एवं वन, विभाग /खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग /स्वास्थ, विभाग /उद्योग, विभाग /श्रम संसाधन, विभाग /लधु जल संसाधन, विभाग /पंचायती राज, विभाग /लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विभाग /योजना एवं विकास, विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग /पथ निमाण, विभाग / ग्रामीण विकास, विभाग /ग्रामीण कार्य, विभाग /समाज कल्याण, विभाग /गन्ना उद्योग, विभाग /नगर विकास एवं आवास, विभाग एवं जल संसाधन विभाग ।

पटना–15, दिनांक– 1.7.16

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक का अनु0जनजाति उपयोजना (TSP) के तहत उद्व्यय एवं व्यय के संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबध में कहना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक 11015/7/2016-SG-II दिनांक 06.05.16(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक का अनु0जनजाति उपयोजना (TSP) के तहत उद्व्यय एवं व्यय के संबंधित सूचना की मॉग की गई है ।

अतः अनुरोध है संलग्न प्रपत्र में सूचना प्रतिवेदन विभाग को शीध्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि समेकित प्रतिवेदन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जा सकें ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन

निदेशक 6/16

No. 11015/07/2016-SG-II
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(SG Division)
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 10.05.2016

To,

Principal Secretaries / Secretaries
Tribal / Social Welfare Departments
State Governments

Subject: Furnishing of information regarding Tribal Sub-Plan (TSP) allocation and expenditure.

Sir,

I am to say that TSP is an important instrument for tribal development in the States. In order to deal with various Parliamentary matters and other reports, data regarding TSP allocation and expenditure is required on day to day basis. It is therefore requested to kindly provide the following information to the Ministry on an urgent basis in the following tables:

(i) Total TSP Allocation and Expenditure

Year	Total Plan Outlay	% ST Population in the State	TSP Allocation	TSP Expenditure
2012-13				
2013-14				
2014-15				
2015-16				
2016-17				

(ii) Sectoral TSP Allocation and Expenditure

Sector	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	Allocation	Expenditure	Allocation	Expenditure	Allocation	Expenditure	Allocation
Education							
Health							
Housing							
Electrification							

Drinking Water & Sanitation							
Agriculture & Allied Activities							
Irrigation							
Livelihood and income generation activities							
Skill Development							
Road Connectivity							
IT & Mobile Connectivity							
Market Development							

2. This may be given priority and the requisite information may be sent in word format through E-mail at nadeem.ahmad@nic.in

Yours faithfully,

(Nadeem Ahmad) 10/3/16
Under Secretary to the Government of India
Tele: 23073708

Issued by speed post
11/3/2016

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

2016–17 में निर्धारित राज्य योजना उद्व्यय (केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि सहित) के विरूद्ध बजट में प्रावधान की गयी राशि का ब्यौरा

	Summary (Head-SCSP-789)	
क्रमांक	विभाग का नाम	बजट राशि (रु0 लाख
1	2	3
1	कृषि विभाग	41105.20
2	पशु एवं मत्सय विभाग	6321.36
3	भवन निर्माण विभाग	28343.84
4	सहकारिता विभाग	9934.04
5	पंचायती राज विभाग	30113.20
6	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	21216.34
7	पर्यावरण एवं वन विभाग	21863.97
8	स्वास्थ्य विभाग	106978.40
9	शिक्षा विभाग	172702.24
10	उद्योग विभाग	14511.53
11	श्रम संसाधन विभाग	9694.70
12	योजना एवं विकास विभाग	47839.54
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	26713.70
14	ग्रामीण कार्य विभाग	130994.80
15	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2175.08
16	पथ निर्माण विभाग	56514.10
17	ग्रामीण विकास विभाग	135581.96
18	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	528.00
19	गन्ना उद्योग विभाग	7503.64
20	नगर विकास एवं आवास विभाग	24097.40
21	लघु जल संसाधन विभाग	9100.32
22	समाज कल्याण विभाग	89708.34
23	योग	993541.70
	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण	90775.00
	कुल योग	**1084316.70**

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

SCSP-789

2016–17 में निर्धारित राज्य योजना उद्व्यय (केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि सहित) के विरूद्ध बजट में प्रावधान की गयी राशि का ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	01	789	0117– बीज उत्पादन कार्यक्रम	3000.00
2	कृषि विभाग	01	789	0120–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	3500.00
3	कृषि विभाग	01	789	0125–बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	3400.00
4	कृषि विभाग	01	789	0126–जैविक खेती का उन्नयन	2595.00
5	कृषि विभाग	01	789	0130–उद्यान विकास योजना	1000.00
6	कृषि विभाग	01	789	0132–एग्रीविजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	504.60
7	कृषि विभाग	01	789	0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0ए0सी0ए)	4474.80
8	कृषि विभाग	01	789	0234–राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	52.00
9	कृषि विभाग	01	789	0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन	600.00
10	कृषि विभाग	01	789	0236–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1242.00
11	कृषि विभाग	01	789	0237–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1800.00
12	कृषि विभाग	01	789	0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	825.60
13	कृषि विभाग	01	789	0239–प्रधान मंत्री कृषि योजना सिंचाई	1200.00
14	कृषि विभाग	01	789	0240–नेशलन ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	42.80
15	कृषि विभाग	01	789	0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई) (ए0सी0ए)	2893.20
16	कृषि विभाग	01	789	0323–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1200.00
17	कृषि विभाग	01	789	0334–राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	34.60
18	कृषि विभाग	01	789	0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन	400.00
19	कृषि विभाग	01	789	0336–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	828.40
20	कृषि विभाग	01	789	0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	550.38
21	कृषि विभाग	01	789	0339–प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	800.00
22	कृषि विभाग	01	789	0340–नेशनल ई–गवर्नेस प्लान–कृषि	28.52
23	कृषि विभाग	01	789	0101–भूमि संरक्षण कार्य	800.00
24	कृषि विभाग	01	789	0202–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	2000.00
25	कृषि विभाग	01	789	0302–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	1333.30
26	कृषि विभाग	01	789	0103–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	5000.00
27	कृषि विभाग	01	789	0107– मिट्टी बीज एवं उर्वक प्रयोशाला का सुदृढ़ीकरण	200.00
28	कृषि विभाग	01	789	0101–कृषि ऋण पर ट्याज अनुदान	400.00
29	कृषि विभाग	01	789	0101–कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	400.00
				योग	**41105.20**

क्रमांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0102–बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	1140.00
2	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0102–बैंक यार्ड मुर्गी पालन योजना	1400.00
3	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0206–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	216.00
4	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0207–राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	24.00
5	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0306–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	144.00
6	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0307–राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	16.00
7	पशु एवं मत्सय विभाग	02	789	0101–ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ	1900.00
8	पशु एवं मत्सय विभाग		789	0101–मछुआरों की सहायता	1481.36
				योग	**6321.36**
1	भवन निर्माण विभाग	03	789	0101–अनुसूचित जाति कै भवन	24243.84
2	भवन निर्माण विभाग	03	789	0102–कृषि कार्यालय भवन	1000.00
3	भवन निर्माण विभाग	03	789	0106–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	3000.00
4	भवन निर्माण विभाग	03	789	0305–कोशल विकास योजना	100.00
				योग	**28343.84**
1	सहकारिता विभाग	09	789	0109–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि की प्रोमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	32.04
2	सहकारिता विभाग	09	789	0110–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों के बीममित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	9900.00
3	सहकारिता विभाग	09	789	0111– पायलट मौसम अधारित फसल बीमा	1.00
4	सहकारिता विभाग	09	789	0122–संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1.00
				योग	**9934.04**
1	पंचायती राज विभाग	16	789	0104–ग्राम कचरी के निर्वाचित प्रतिनिधियो की नियत भत्ता हेतु	2685.20
2	पंचायती राज विभाग	16	789	0105–पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियव भत्ता हेतु	300.00
3	पंचायती राज विभाग	16	789	0106–जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत	50.00
4	पंचायती राज विभाग	16	789	0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना	20778.00
5	पंचायती राज विभाग	16	789	0113–पंचायती राज यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाह्य सम्पोषित योजना)	6300.00
				योग	**30113.20**
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	18	789	0302–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	**21216.34**
				योग	*21216.34*
1	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	789	0101–अवकृष्ट वनों का पुर्नवास	936.00
2	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	789	0102–नहर तट फार्म	465.00
3	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	789	0103–पथ तट फार्म	462.97
4	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	789	0201–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20000.00

मांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
				योग	**21863.97**
1	स्वास्थ्य विभाग	20	789	0201–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20000.00
2	स्वास्थ्य विभाग	20	789	0301–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1500.00
3	स्वास्थ्य विभाग	20	789	0201–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	44187.04
4	स्वास्थ्य विभाग	20	789	0301–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1291.36
5	स्वास्थ्य विभाग	20	789	0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु	40000.00
				योग	**106978.40**
1	शिक्षा विभाग	21	789	0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना	5200.00
2	शिक्षा विभाग		789	0306–प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्य{म (एमडीएम)	67300.01
3	शिक्षा विभाग	21	789	0308–सर्वशिक्षा अभियान (एस0एस0ए)	82202.23
4	शिक्षा विभाग	21	789	0101–मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	2500.00
5	शिक्षा विभाग	21	789	0104–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	2500.00
6	शिक्षा विभाग		789	0305–ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की सीपना की स्कीम	500.00
7	शिक्षा विभाग	21	789	0101–प्रौढ़ शिक्षा	10000.00
8	शिक्षा विभाग		789	0101– राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	2500.00
				योग	**172702.24**
1	उद्योग विभाग	23	789	0101–विद्युत करघा योजना	43.00
2	उद्योग विभाग	23	789	0104–हस्तकरघा विकास की योजना	1480.00
3	उद्योग विभाग	23	789	0109–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदा	400.00
4	उद्योग विभाग	23	789	0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की सीपना	11904.56
5	उद्योग विभाग	23	789	0103–सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जिरियंगि एण्ड टेक्नोलॉजी की सीपना	10.00
6	उद्योग विभाग	23	789	0101–हस्तकरघा–भवन	230.00
7	उद्योग विभाग	23	789	0102–रेशम–भवन	250.00
8	उद्योग विभाग	23	789	0101–क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	193.97
				योग	**14511.53**
1	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0101–ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	30.70
2	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0102–बंथुआ मजदूर कल्याण कार्य{म	55.00
3	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0103–अन्तर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	70.00
4	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0104–बाल श्रमिक तंत्र का सुदढ़ीकरण	100.00
5	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0101–बिहार कौशल विकास मिशन	8839.00
6	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0110–असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजि सुरक्षा	300.00
7	श्रम संसाधन विभाग	26	789	0101–असंगठित मजदूरी एवं शिल्पकारो की सामाजिक सुरक्षा	300.00

क्रमांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
				योग	**9694.70**
1	योजना एवं विकास विभाग	35	789	0101–आपातकालीन कोशी पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक	12867.04
2	योजना एवं विकास विभाग	35	789	0106– मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	22994.50
3	योजना एवं विकास विभाग	35	789	0103–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	10176.00
4	योजना एवं विकास विभाग	35	789	0202–सीमा क्षेत्र विकास बार्यक्रम योजना (बी0ए0डी0पी0)	1166.00
5	योजना एवं विकास विभाग	35	789	0202–सीमा क्षेत्र विकास बार्यक्रम योजना	636.00
				योग	**47839.54**
1	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0102–ग्रामीण जलापूर्ति योजना	200.00
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0104–ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड	547.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0111–ग्रामीण जलापूर्ति योजना–(ट्यूबवेलल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	105.00
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0212–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	8842.50
5	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0213–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	7752.20
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789		6067.00
7	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	36	789	0313–निर्मल भारत अभियान	3200.00
				योग	*26713.70*
	ग्रामीण कार्य विभाग	37	**789**	**0104–मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना**	130994.80
1	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40	789	0101–भूमि अंर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	2075.08
2	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40	789	0104–गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण	100.00
3				**योग**	*2175.08*
1	*पथ निर्माण विभाग*	*41*	***789***	***0103–मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना***	*56514.10*
1	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0103–मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	18914.18
2	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0302–इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)	17530.63
3	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0202–राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (एन0आर0एल0एम)	17676.40
4	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0202–राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (एन0आर0एल0एम)	7694.22
5	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0301–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	63220.32
6	ग्रामीण विकास विभाग	42	789	0301–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	10546.21
				योग	135581.96
1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	42	789	0110–बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना–विश्व बैंक सम्पोषित–ग्रामीण विकास विभाग हेतु	528.00
				योग	528.00
1	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0108–ईख विकास	
2	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0101–आर्थिक विकास	320.00

ांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
3	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0101–पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1207.64
4	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0102–पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	2000.00
5	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0103–पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	2000.00
6	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0101–नाली निर्मण एवंमल किनासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	720.00
7	गन्ना उद्योग विभाग	45	789	0203–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम	200.00
				योग	7503.64
1	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	0102–परिवहन के लिए शहरी सीनीय निकायों को सहायक अनुदान	2000.00
2	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	7000.00
3	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	0202–जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएमएसीए)	2271.00
4	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	0302–जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएमएसीए)	11500.00
5	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	*1000.00*
6	*नगर विकास एवं आवास विभाग*	*48*	*789*	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	*326.40*
				योग	*24097.40*
1	जल संसाधन विभाग	49	789	*0101–उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ*	6077.16
2	लघु जल संसाधन विभाग	50	789	0103–जमीन्दारी बाँधों का जीर्णोद्धार	1000
3	लघु जल संसाधन विभाग	50	789	0101–बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	44.32
4	लघु जल संसाधन विभाग	50	789	0101–निजी नलकूप	1629.20
5	लघु जल संसाधन विभाग	50	789	0101–लघु सिंचाई योजना	6426.80
				योग	*9100.32*
1	समाज कल्याण विभाग	51	789	0103–आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	800.00
2	समाज कल्याण विभाग	51	789	0104–कबीर अन्त्येनिष्ट अनुदान योजना	400.00
3	समाज कल्याण विभाग	51	789	0107–मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	1500.00
4	समाज कल्याण विभाग	51	789	0108–मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	1060.00
5	समाज कल्याण विभाग	51	789	0109–मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	615.00
6	समाज कल्याण विभाग	51	789	0111–मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	300.00
7	समाज कल्याण विभाग	51	789	0312–किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	51.00
8	समाज कल्याण विभाग	51	789	0313–इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	40.00
9	समाज कल्याण विभाग	51	789	0205–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी)	39223.80

क्रमांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
10	समाज कल्याण विभाग	51	789	0305–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी)	1500.00
	समाज कल्याण विभाग	51	789	0102–लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3000.00
	समाज कल्याण विभाग	51	789	0103–बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2500
	समाज कल्याण विभाग	51	789	0104–राज्य वृद्वावस्था पेंशन योजना	300
	समाज कल्याण विभाग	51	789	0204–एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)	38418.54
	समाज कल्याण विभाग	51	789	0304–एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)	
				योग	**89708.34**
	अनुसूचित जाति विभाग	42	789	0201–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	63220.32
	अनुसूचित जाति विभाग	42	789	0201–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	10546.21
	अनुसूचित जाति विभाग	42	789	0110–बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना–विश्व बैंक सम्पोषित–ग्रामीण विकास विभाग	528
				योग	**74294.53**

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

2016–17 में निर्धारित राज्य योजना उद्व्यय (केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि सहित) के विरूद्ध बजट में प्रावधान की गयी राशि का ब्यौरा

क्रमांक	Summary (Head-TSP-796)	
1	2	3
1	कृषि विभाग	4359.65
2	पशु एवं मत्सय विभाग	1974.41
3	भवन निर्माण विभाग	*1800.00*
4	सहकारिता विभाग	993.40
5	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2121.63
6	पर्यावरण एवं वन विभाग	116.50
7	स्वास्थ्य विभाग	*46697.84*
8	शिक्षा विभाग	10950.14
9	उद्योग विभाग	*1431.76*
10	श्रम संसाधन विभाग	430.94
11	योजना एवं विकास विभाग	1861.10
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2651.34
13	ग्रामीण कार्य विभाग	11908.62
14	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	138.34
15	ग्रामीण विकास विभाग	19440.54
16	समाज कल्याण विभाग	14917.79
	योग	121794.00
17	02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	12280.00
	कुल योग	**134074.00**

TSP-796

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

2016–17 में निर्धारित राज्य योजना उद्व्यय (केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि सहित)

के विरूद्ध बजट में प्रावधान की गयी राशि का ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	मांग सं0	लघु शीर्ष		बजट राशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	01	796	0134–इनटेनसिफाईड फिल्ड डेवलपमेट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई याजना	240.00
2	कृषि विभाग	01	796	0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम	300.00
3	कृषि विभाग	01	796	0143–प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	350.00
4	कृषि विभाग	01	796	0147–बाड़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	340.00
5	कृषि विभाग	01	796	0147–जैविक खेती का उननयन	259.54
6	कृषि विभाग	01	796	0152–उद्यान विकास योजना	100.00
7	कृषि विभाग	01	796	0154–एग्रीविजनस इन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना	50.46
8	कृषि विभाग	01	796	0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0ए0सी0ए)	447.48
9	कृषि विभाग	01	796	0256–राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	5.20
10	कृषि विभाग	01	796	0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन	60.00
11	कृषि विभाग	01	796	0257–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	82.56
12	कृषि विभाग	01	796	0259–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	180.00
13	कृषि विभाग	01	796	0260–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	124.26
14	कृषि विभाग	01	796	0261–प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	120.00
15	कृषि विभाग	01	796	0262–नेशनल ई–गर्वनेस प्लान–कृषि	4.28
16	कृषि विभाग	01	796	0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई) (ए0सी0ए)	298.32
17	कृषि विभाग	01	796	0356–राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	3.46
18	कृषि विभाग	01	796	0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन	40.00
19	कृषि विभाग	01	796	0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	55.04
20	कृषि विभाग	01	796	0359–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	120.00
21	कृषि विभाग	01	796	0360–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	82.84
22	कृषि विभाग	01	796	0361–प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	80.00
23	कृषि विभाग	01	796	0362–नेशनल ई–गवर्नेस प्लान कृषि	2.88
24	कृषि विभाग	01	796	0108–भूमि संरक्षण कार्य	80.00
25	कृषि विभाग	01	796	0209–एकीकृत जल संभर प्रबधन कार्यक्रम	200.00
26	कृषि विभाग	01	796	0309–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम	133.33
27	कृषि विभाग	01	796	0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	500.00
28	कृषि विभाग	01	796	0105–मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	20.00
29	कृषि विभाग	01	796	0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	40.00
30	कृषि विभाग	01	796	0101–कृषि कार्यालय भवनों की सीपना	40.00
				योग	**4359.65**
31	पशु एवं मत्सय विभाग	02	796	0124–बैक याड बकरी पालन योजना	310.00
32	पशु एव मत्सय विभाग	02	796	0125–बैक याड मुर्गी पालन योजना	500.00
33	पशु एवं मत्सय विभाग	02	796	0101–प्रशिक्षण एवं विस्तार	570.00
34	पशु एवं मत्सय विभाग	02	796	0109–मछुआरों की सहायता	444.41
35	पशु एवं मत्सय विभाग	03	796	0105–कृषि कार्यालय भवन	100.00